Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

18 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने लखनऊ में 'नमस्ते दिवस' पर कचरा बीनने वालों के लिए हेल्पलाइन 14473 शुरू की।

16 जुलाई, 2025 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई, जहाँ केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कचरा बीनने वालों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 14473 का अनावरण किया। यह शुभारंभ 'नमस्ते दिवस' के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान हुआ। यह राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र पहल है, जिसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के कल्याण और सीवर/सेप्टिक सफाई कार्यों के मशीनीकरण पर केंद्रित है।

• हेल्पलाइन लॉन्च कार्यक्रम का नेतृत्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के अंतर्गत राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने किया, और इसमें सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (SSW) और कचरा बीनने वालों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट और आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मशीनीकृत स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अग्रिम पंक्ति के सफाई कर्मचारियों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना था।

• इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार योगिता स्वरूप और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) में भारत की प्रतिनिधि एंजेला लुसिगी सहित कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ राज्य और केंद्र सरकारों के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। उनकी भागीदारी ने स्वच्छता कार्यबल की स्थिति में सुधार के लिए वैश्विक साझेदारी के महत्व पर ज़ोर दिया।

Key Points:-

(i) नमस्ते योजना के तहत, बी.एल. वर्मा ने अब तक 85,067 सीवर सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की सफल प्रोफाइलिंग की घोषणा की। 45,871 सीवर सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को पीपीई किट वितरित किए गए हैं और 40,166 कर्मचारियों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए हैं, जो भारत के स्वच्छता कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

(ii) कार्यक्रम में एक संवर्धित वास्तविकता (AR)/आभासी वास्तविकता (VR) प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया गया, जिसे व्यावसायिक सुरक्षा प्रथाओं में SSWs को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नमस्ते पहल के तहत PPE किट की सुरक्षा और कार्यक्षमता को रचनात्मक रूप से उजागर करने और सहभागिता के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए एक फैशन शो का भी आयोजन किया गया।

(iii) इसके अतिरिक्त, आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ERSUs) के लिए विशेष सुरक्षा उपकरण वितरित किए गए, जिससे स्वच्छता संबंधी संकट स्थितियों के लिए तत्परता सुनिश्चित हुई। यह नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा और मशीनीकरण को सुनिश्चित करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है।

2. मैसूर सुपर स्वच्छ लीग में शामिल, बेंगलुरु राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में 36वें स्थान पर।

जुलाई 2025 में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग जारी की, जिसमें मैसूरु के प्रतिष्ठित सुपर स्वच्छ लीग में प्रवेश और बेंगलुरु के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 36वें स्थान पर पहुंचने पर प्रकाश डाला गया - जो शहरी स्वच्छता उत्कृष्टता के लिए कर्नाटक के मजबूत प्रयास को दर्शाता है।

• तीन से दस लाख की आबादी वाले मैसूर ने सुपर स्वच्छ लीग में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है। यह लीग उन शहरों का एक विशिष्ट समूह है जिन्होंने लगातार स्वच्छता में सर्वोच्च प्रदर्शन किया है। यह सम्मान नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (SBM-U) के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान किए।

• इस बीच, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) द्वारा शासित बेंगलुरु ने 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 2023-24 में 125वें स्थान से 36वें स्थान पर उल्लेखनीय तरक्की की है। शहर को 10,000 में से 5,642 अंक मिले हैं, जहाँ कचरा पृथक्करण 82% है, जबकि आवासीय और व्यावसायिक स्वच्छता लगभग पूर्ण स्तर पर पहुँच गई है।

• अपनी प्रगति के बावजूद, बेंगलुरु अभी भी सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में समस्याओं से जूझ रहा है, जिसका स्कोर 87% से गिरकर 27% हो गया है, तथा लैंडफिल साइटों की समस्या से जूझ रहा है, जिनका स्कोर शून्य है, जो BBMP द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों को रेखांकित करता है।

Key Points:-

(i) नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह का नेतृत्व केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य मंत्री तोखन साहू ने किया, जिन्होंने जन भागीदारी, समुदाय-नेतृत्व वाले प्रयासों और डिजिटल स्वच्छता निगरानी के महत्व पर जोर दिया, जिसने मैसूर के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(ii) स्वच्छ सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि मैसूर ने 100% से अधिक अपशिष्ट पृथक्करण और स्वच्छता सेवाओं में उच्च मानकों का प्रदर्शन किया, जिसमें अग्रिम पंक्ति के सफाई कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त था, जिनकी प्रतिबद्धता और सामुदायिक सहभागिता की पुरस्कार समारोह के दौरान सराहना की गई।

(iii) कुल मिलाकर, ये परिणाम बेंगलुरु और मैसूरु दोनों को SBM-U के तहत कर्नाटक की प्रगतिशील उपलब्धियों के उदाहरण के रूप में दर्शाते हैं, साथ ही बड़े शहरी केंद्रों में सार्वजनिक स्वच्छता और लैंडफिल सुधार पर निरंतर ध्यान देने की बढ़ती आवश्यकता का संकेत देते हैं।

3. गुजरात ने वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की।

गुजरात सरकार ने 16 जुलाई, 2025 को गांधीनगर में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना (TGSP) शुरू की। इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा विश्लेषण के माध्यम से जनजातीय समुदायों में प्रचलित वंशानुगत बीमारियों को समझने और उनसे निपटने के लिए एक व्यापक आनुवंशिक संदर्भ डेटाबेस तैयार करना है।

- **"गुजरात में जनजातीय आबादी के लिए संदर्भ जीनोम डेटाबेस का निर्माण" नामक परियोजना का क्रियान्वयन गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (GBRC) द्वारा विभिन्न राज्य विभागों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के तकनीकी सहयोग से किया जाएगा। यह पहल जनजातीय आबादी के लिए व्यक्तिगत चिकित्सा में सहायता के लिए आनुवंशिक विकारों और आनुवंशिक मार्करों की पहचान पर केंद्रित होगी।**

- **इस परियोजना का उद्देश्य सिकल सेल, थैलेसीमिया, कैंसर जैसी बीमारियों का शीघ्र पता लगाने के लिए गुजरात-व्यापी आनुवंशिक डेटाबेस बनाना और बेहतर जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल समाधानों के लिए प्रतिरक्षा मार्करों की पहचान करना है।**

- **इस पहल के तहत, गुजरात के 17 ज़िलों के 20 से ज़्यादा आदिवासी समुदायों के कुल 2,000 व्यक्ति जीनोम अनुक्रमण में भाग लेंगे। यह अध्ययन 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है और परिवारों में आनुवंशिक पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए त्रि-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है—जिसमें माता-पिता और एक बच्चे दोनों शामिल होते हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण विविध आनुवंशिक लक्षणों और अंतर-पीढ़ीगत विरासत प्रवृत्तियों को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**

Key Points:-

(i) भाग लेने वाले आदिवासी समुदायों में बामचा, गरासिया भील, ढोली भील, चौधरी, भांका, तड़वी, वावली, दुबला, गामित, गोंड, कथोड़ी, कुकना, कुनबी, नायका, पारधी, पटेलिया, राठवा, वारली, कोटवलिया और अन्य शामिल हैं। विशेष रूप से, आर्मेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट जैसे क्षेत्रों से अपने अफ्रीकी वंश के लिए जाना जाने वाला सिद्दी समुदाय भी इस आनुवंशिक मानचित्रण पहल का हिस्सा होगा।

(ii) प्रत्येक जनजाति से कम से कम एक आनुवंशिक तिकड़ी (पिता, माता और बच्चा) अध्ययन में शामिल होगी, और प्रतिभागियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होगी। केवल दृश्यमान रक्त विकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ और स्वास्थ्य जाँच सुविधाएँ सटीक, जनजाति-आधारित जीनोमिक अनुसंधान सुनिश्चित करेंगी।

4. कैबिनेट ने PM धन-धान्य कृषि योजना और ₹27,000 करोड़ हरित ऊर्जा निवेश को मंजूरी दी।

16 जुलाई, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई ऐतिहासिक प्रस्तावों को मंज़ूरी दी, जिनमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) नामक एक विशाल कृषि योजना, NTPC लिमिटेड और NLCIL द्वारा प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा निवेश, और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उपलब्धि का जश्न मनाने वाला एक प्रस्ताव शामिल है। ये निर्णय कृषि, हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान में सरकार के बहु-क्षेत्रीय प्रयासों को दर्शाते हैं।

• कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) को 2025-26 से 2031-32 तक की छह वर्षीय अवधि के लिए 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ मंज़ूरी दे दी है। यह योजना 11 केंद्रीय विभागों की 36 मौजूदा कृषि योजनाओं को समेकित और एकीकृत करती है, जिससे तालमेल स्थापित होता है, दोहराव से बचा जा सकता है और किसानों के परिणामों में सुधार होता है। यह कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय को युक्तिसंगत बनाने और लक्षित समर्थन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) NLC इंडिया लिमिटेड (NLCIL) के लिए निवेश छूट को भी मंजूरी दे दी है, जिससे वह अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगी। इस छूट से NLCIL और NIRL को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लोक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा निर्धारित 30% निवल मूल्य सीमा को पार करने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा में तेज़ और बड़े निवेश की सुविधा होगी।

• हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, CCEA ने NTPC लिमिटेड को अधिक शक्तियाँ सौंपने को मंज़ूरी दे दी है, जिससे कंपनी अपनी हरित ऊर्जा शाखा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) और उसकी सहायक कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकेगी। इससे पूरे भारत में नई नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता स्थापित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, NTPC, भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

Key Points:-

(i) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना अधिकारी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर 18 दिनों के ऐतिहासिक मिशन, एक्सिओम-4 के सफल समापन के लिए सम्मानित करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया। उनकी भागीदारी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग और मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान में भारत की बढ़ती भूमिका को चिह्नित किया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय वायु सेना अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय मानवयुक्त मिशन के बाद कैबिनेट द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है।

(ii) PM-DDKY योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW), ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जैसे मंत्रालयों की योजनाओं को एकीकृत करेगी। यह एक एकीकृत प्रशासनिक ढाँचे के अंतर्गत बुनियादी ढाँचा समर्थन, जलवायु-अनुकूल खेती, सिंचाई संवर्धन

और कटाई-पश्चात प्रबंधन जैसे घटक प्रदान करेगी।

(iii) ये निर्णय सरकार के तीन मोर्चों पर ध्यान केंद्रित करने पर केंद्रित हैं—कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में तेज़ी लाना और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत के वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा देना। अकेले इस तिथि तक हरित ऊर्जा क्षेत्रों में स्वीकृत कुल निवेश 27,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जो इस वर्ष की सबसे वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठकों में से एक है।

INTERNATIONAL

1. भारत ने शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही पर संयुक्त राष्ट्र मित्र समूह की बैठक की सह-अध्यक्षता की।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय मित्र समूह (GoF) बैठक की सह-अध्यक्षता की, जिसमें दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए न्याय और जवाबदेही के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

• भारत ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालय में बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल के साथ शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही हेतु मित्र समूह (GoF) की जुलाई 2025 की बैठक की सह-अध्यक्षता की।

• बैठक का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने किया और इसमें लगभग 40 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों, वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों और कानूनी क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

• बैठक में शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों में दंडमुक्ति को संबोधित करने, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचों को मज़बूत करने और अंतर-सरकारी सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसमें शांति सैनिकों को निशाना बनाने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए मज़बूत न्यायिक प्रणालियों और प्रभावी प्रवर्तन तंत्रों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।

Key Points:-

(i) इस कार्यक्रम में दोहराया गया एक प्रमुख संदेश यह था कि जवाबदेही सुनिश्चित करने से न केवल पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिलता है, बल्कि दुनिया भर में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सुरक्षा, संचालन संबंधी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता भी बढ़ती है। यह जवाबदेही सैन्य योगदान देने वाले देशों और स्थानीय समुदायों, दोनों के बीच विश्वास का निर्माण करती है।

(ii) संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े संचयी योगदानकर्ता के रूप में, भारत ने पिछले 70 वर्षों में वैश्विक मिशनों में 3,00,000 से अधिक कर्मियों को भेजा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के लगभग हर प्रमुख शांति अभियान में सेवा करते हुए 182 भारतीय शांति सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जो वैश्विक शांति के प्रति देश की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(iii) शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों हेतु जवाबदेही हेतु जीओएफ की स्थापना दिसंबर 2022 में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना यूएनएससी प्रस्ताव 2589 (2021) के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए

की गई थी, जिसमें शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराध करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का आह्वान किया गया था और सदस्य देशों को कानूनी जवाबदेही की दिशा में कड़े कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

BANKING & FINANCE

1. उद्योग जगत की आलोचना के बीच HSBC संयुक्त राष्ट्र समर्थित नेट-जीरो बैंकिंग गठबंधन से बाहर हो गया।

HSBC (हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन) ने जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित NZBA (नेट-जीरो बैंकिंग एलायंस) से आधिकारिक तौर पर बाहर निकलने का फैसला किया है। गठबंधन की जलवायु प्रतिबद्धताओं में हाल ही में दी गई ढील के बाद रणनीतिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए यह फैसला लिया गया है।

• दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग और वित्तीय सेवा संगठनों में से एक, HSBC, जुलाई 2025 में NZBA (नेट-ज़ीरो बैंकिंग अलायंस) से हट गया है। यह निर्णय एनजेडबीए के ढाँचे में हाल ही में हुए बदलावों के बाद लिया गया है, जिसमें जलवायु लक्ष्यों को 1.5°C के लक्ष्य से घटाकर 2°C कर दिया गया है और 2050 की नेट-ज़ीरो आवश्यकता को हटा दिया गया है। HSBC ने कहा कि उसने अपनी आंतरिक परिवर्तन रणनीति विकसित कर ली है और अब उसे गठबंधन-आधारित मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है।

• NZBA की शुरुआत अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित GFANZ (ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट ज़ीरो) के तहत की गई थी ताकि बैंकिंग क्षेत्र को पेरिस समझौते के वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लक्ष्य के अनुरूप बनाया जा सके। HSBC के बाहर निकलने के साथ, सदस्य बैंकों की कुल पूंजी अब 74 ट्रिलियन डॉलर से घटकर 44 ट्रिलियन डॉलर रह गई है। इससे पहले 2025 में, जेपी मॉर्गन चेज़, सिटीग्रुप, मॉर्गन स्टेनली और बैंक ऑफ अमेरिका सहित प्रमुख अमेरिकी बैंक भी राजनीतिक और नियामक जटिलताओं का हवाला देते हुए इस गठबंधन से हट गए थे।

• NZBA से हटने के बावजूद, HSBC ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई। इसने पुष्टि की कि वह 2050 तक अपने वित्तपोषित पोर्टफोलियो में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बैंक की योजना 2025 के अंत तक एक संशोधित "शुद्ध-शून्य संक्रमण योजना" प्रकाशित करने की है, जो विज्ञान-आधारित लक्ष्यों और क्षेत्र-विशिष्ट रोडमैप पर आधारित होगी। HSBC ने यह भी कहा कि वह वित्तपोषित उत्सर्जन को मापना जारी रखेगा, हितधारकों को पारदर्शी रूप से रिपोर्ट करेगा, और IEA (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी) जैसे विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना रहेगा।

Key Points:-

(i) इस कदम की जलवायु वकालत करने वाले समूह शेयरएक्शन और £1.2 ट्रिलियन से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले संस्थागत निवेशकों ने तीखी आलोचना की। इन समूहों ने चिंता व्यक्त की कि HSBC का एक संरचित वैश्विक जलवायु मंच से हटना

अन्य बैंकों के लिए एक नकारात्मक संकेत होगा और जलवायु जवाबदेही को मानकीकृत करने के वैश्विक प्रयासों को कमजोर करेगा। शेयरएक्शन ने कहा कि यह कदम "बेहद निराशाजनक" है और इससे बैंकों की स्वैच्छिक शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धताओं में जनता का विश्वास कमज़ोर हो सकता है, खासकर स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय विनियमन या प्रवर्तन के अभाव में।

(ii) HSBC का यह निर्णय वैश्विक वित्तीय उद्योग में व्यापक रुझानों को भी दर्शाता है, जहाँ बैंकों को बढ़ते राजनीतिक, नियामक और प्रतिष्ठा संबंधी दबावों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, ESG(पर्यावरण, सामाजिक और शासन) विरोधी भावना—खासकर रिपब्लिकन नेतृत्व वाले राज्यों में—के कारण जलवायु-केंद्रित वित्तीय गठबंधनों पर मुकदमे, विनिवेश और नियामक जाँच हुई है। इसने बैंकों को NZBA जैसे स्वैच्छिक गठबंधनों के साथ सार्वजनिक जुड़ाव पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है, जबकि जलवायु जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। HSBC के इस कदम को इस व्यापक रणनीतिक पुनर्संतुलन का एक हिस्सा माना जा रहा है।

(iii) हालाँकि अब NZBA का हिस्सा नहीं है, HSBC कई वैश्विक और राष्ट्रीय जलवायु वित्त पहलों में शामिल है। यह UK के TPT (ट्रांज़िशन प्लान टास्कफोर्स) में भाग लेता रहता है, GFANZ नेटवर्क का समर्थन करता है, और UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) के नेतृत्व में परामर्श में योगदान देता है। बैंक का मानना है कि बहुपक्षीय निकासी का मतलब जलवायु परिवर्तन से अलगाव नहीं है। इसके बजाय, इसका लक्ष्य वैश्विक रिपोर्टिंग मानदंडों और क्षेत्र-विशिष्ट उत्सर्जन न्यूनीकरण प्रक्षेप पथों का पालन करते हुए अपनी जलवायु रणनीति को स्वतंत्र रूप से लागू करना है।

2. IRDAI पैनल ने पॉलिसीधारकों की सुरक्षा के लिए बीमा और गैर-बीमा कंपनियों के बीच विलय पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की।

IRDAI
Insurance Regulatory and Development Authority

17 जुलाई, 2025 को, IRDAI (भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण) ने पॉलिसीधारकों की सुरक्षा के लिए बीमा और गैर-बीमा कंपनियों के बीच विलय पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश की। इस पैनल की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने की।

- **फरवरी 2025 में, IRDAI ने बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन का आकलन करने और प्रस्ताव करने के लिए सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस पहल का उद्देश्य नियामक अंतराल का मूल्यांकन करना और क्षेत्रीय परिवर्तनों के बीच पॉलिसीधारक सुरक्षा सुनिश्चित करना था।**

- **पैनल ने हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित IRDAI की 132वीं बैठक के दौरान अपनी गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। चर्चा मुख्य नियामक सुरक्षा उपायों और विभिन्न क्षेत्रों में विलय की अनुमति देने में संभावित संरचनात्मक जोखिमों पर केंद्रित रही।**

- **पैनल ने चेतावनी दी कि बीमा कंपनियों और गैर-बीमा कंपनियों के बीच विलय से नैतिक जोखिम पैदा हो सकते हैं। इनमें धन का संभावित दुरुपयोग, हितों का टकराव और मिश्रित व्यावसायिक मॉडल में पॉलिसीधारकों के लिए सुरक्षा तंत्र में समझौता शामिल है।**

Key Points:-

(i) पैनल के अनुसार, ऐसे विलयों की अनुमति देने से

अनुचित लाभ या अंदरूनी लाभ के ज़रिए क्षेत्रीय अखंडता ख़तरे में पड़ सकती है। इससे नियामक जाँच कमज़ोर हो सकती है और बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में दीर्घकालिक विश्वास प्रभावित हो सकता है।

(ii) संभावित उल्लंघनों से निपटने के लिए, IRDAI ने अपने पूर्णकालिक सदस्यों से युक्त निर्णायक पैनल गठित किए हैं। इन पैनलों को मानदंडों का उल्लंघन करने वाली बीमा कंपनियों और मध्यस्थों की जाँच करने और उन्हें दंडित करने का अधिकार है, ताकि नियामक प्रवर्तन मज़बूत बना रहे।

(iii) दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, IRDAI ऐसे नियामक फ़ायरवॉल पर भी विचार कर रहा है जो बीमाकर्ताओं और गैर-बीमाकर्ताओं के बीच वित्तीय क्रॉस-स्वामित्व को प्रतिबंधित करें। इसका उद्देश्य प्रणालीगत जोखिमों को रोकना, सॉल्वेंसी निगरानी में सुधार करना और असंबंधित व्यावसायिक जोखिमों और प्रशासनिक विफलताओं से पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना है।

ECONOMY & BUSINESS

1. टेस्ला ने मॉडल Y लॉन्च के साथ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में पहला भारत शोरूम खोला।

टेस्ला इंक. ने मुंबई के आलीशान बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में अपने पहले शोरूम, जिसे "एक्सपीरियंस सेंटर" कहा जाता है, का उद्घाटन करके आधिकारिक तौर पर भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश कर लिया है। 15 जुलाई 2025 को होने वाला यह रणनीतिक लॉन्च, टेस्ला मॉडल वाई SUV के आगमन और इसके फ़ास्ट-चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के शुभारंभ के साथ, भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

• टेस्ला ने मुंबई के BKC स्थित मेकर मैक्सिटी मॉल में 4,000 वर्ग फुट जगह 5 साल के समझौते के तहत ₹35 लाख प्रति माह के किराए पर ली है। इस हाई-प्रोफाइल लोकेशन का उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक के प्रदर्शन और प्रीमियम भारतीय उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए टेस्ला के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करना है। एक्सपीरियंस सेंटर आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई 2025 को खोला जाएगा, जिससे मुंबई भारत में टेस्ला की भौतिक उपस्थिति का प्रवेश द्वार बन जाएगा।

• टेस्ला ने अपनी मॉडल Y SUV के दो वेरिएंट लॉन्च किए: रियर-व्हील ड्राइव (₹59.89 लाख) और लॉन्ग रेंज ऑल-व्हील ड्राइव (₹67.89 लाख)। ये यूनिट्स चीन के शंघाई स्थित टेस्ला की गीगाफैक्ट्री से आयात की गई थीं। भारत में 70% से 100% तक के आयात शुल्क के कारण, कीमतें अभी भी ऊँची हैं। यह कदम टेस्ला की "आयात-प्रथम" रणनीति को दर्शाता है, जबकि भविष्य में स्थानीय रूप से असेंबल किए गए मॉडलों के लिए कम शुल्क पर बातचीत चल रही है।

Key Points:-

(i) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोरूम का उद्घाटन किया और टेस्ला के विस्तार के लिए राज्य सरकार के सहयोग का वादा किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, अनुसंधान एवं विकास (R&D) और बैटरी नवाचार का केंद्र बनने के लिए महाराष्ट्र की तत्परता पर ज़ोर दिया। भारत की FAME-II (इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाना

और उनका निर्माण) पहल के अनुरूप, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत टेस्ला को प्रोत्साहन देने पर चर्चा चल रही है।

(ii) टेस्ला ने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और दिल्ली-NCR सहित प्रमुख शहरी केंद्रों में सात सुपरचार्जर स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। ये फास्ट-चार्जिंग स्टेशन चार्जिंग समय को काफी कम करने के लिए टेस्ला की स्वामित्व वाली तकनीक का उपयोग करेंगे, और आगे चलकर इन्हें ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की देखरेख में राष्ट्रीय ईवी चार्जिंग नेटवर्क के तहत एकीकृत किए जाने की उम्मीद है।

(iii) टेस्ला 2025 की चौथी तिमाही तक दिल्ली में अपना दूसरा शोरूम खोलने की तैयारी कर रही है और भविष्य के बाजारों के रूप में चेन्नई और बेंगलुरु पर विचार कर रही है। हालाँकि, तेज़ विस्तार को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक भारत सरकार के साथ आयात शुल्क में कटौती और एक स्पष्ट इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण नीति को लेकर चल रही बातचीत है। टेस्ला स्थानीय निवेश की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए ऑटोमोबाइल के लिए PLI (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजना पर भी नज़र रख रही है।

2. NABARD ने चेन्नई में 44वें स्थापना दिवस पर NIVARAN पहल, रूरलटेक कोलैब और व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया।

12 जुलाई, 2025 को, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने तमिलनाडु के चेन्नई स्थित ITC ग्रैंड चोला में अपना 44वाँ स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर, NIVARAN, रूरलटेक कोलैब, एक नया व्हाट्सएप चैनल और लेह में एक उप-कार्यालय सहित कई परिवर्तनकारी पहलों का शुभारंभ किया गया। ये पहल ग्रामीण नवाचार, संस्थागत शासन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए NABARD की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

• स्थापना दिवस समारोह के दौरान, NABARD ने रूरलटेक कोलैब नामक एक मुक्त नवाचार डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत की, जो स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और ग्रामीण-तकनीकी डेवलपर्स को सशक्त बनाएगा। यह प्लेटफ़ॉर्म ग्रामीण-केंद्रित तकनीकों के सहयोगात्मक सह-निर्माण, परीक्षण और विस्तार को सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमिता और अनुसंधान एवं विकास अभिसरण के माध्यम से जमीनी स्तर पर नवाचार और ग्रामीण आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है।

• NABARD ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए विशेष रूप से एक केंद्रीकृत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली, निवारण भी शुरू की। यह प्रणाली शिकायत दर्ज करने, समाधान की स्थिति पर नज़र रखने और बेहतर प्रशासन के लिए 24x7 डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करती है। यह प्लेटफ़ॉर्म ग्रामीण

बैंकिंग सेवाओं, विशेष रूप से व्यापक पहुँच वाली सहकारी संस्थाओं में, जवाबदेही और पारदर्शिता को मज़बूत करने के लिए विकसित किया गया है।

• वंचित क्षेत्रों में अपनी भौतिक पहुँच बढ़ाने के लिए, NABARD ने लेह, लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) में एक नए उप-कार्यालय का उद्घाटन किया है। यह रणनीतिक कदम सुदूर हिमालयी क्षेत्रों में औपचारिक ऋण, क्षमता निर्माण और ग्रामीण वित्त तक पहुँच में सुधार लाने के बैंक के दृष्टिकोण के अनुरूप है। लेह उप-कार्यालय उच्च-ऊँचाई वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में विकासात्मक वित्त, क्षेत्रीय पहुँच और प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

Key Points:-

(i) इस कार्यक्रम में आधिकारिक NABARD व्हाट्सएप चैनल का भी शुभारंभ किया गया, जो किसानों और हितधारकों के लिए बाजार सलाह, वित्तीय उत्पाद अपडेट, सरकारी योजनाओं और मूल्य पूर्वानुमान सूचना (PFI) तक वास्तविक समय तक पहुंच प्रदान करता है।

(ii) यह डिजिटल पहल अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है और जमीनी स्तर के लाभार्थियों और कृषि उद्यमियों तक नाबार्ड की सूचना वितरण को बढ़ाती है।

(iii) NABARD के 44वें स्थापना दिवस पर नीतिगत नवाचार, शिकायत निवारण प्रणालियों और तकनीक-संचालित साझेदारियों के माध्यम से सतत ग्रामीण परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया गया। निवारण और रूरलटेक कोलैब जैसी पहलों के साथ, बैंक ने स्टार्टअप्स, राज्य सहकारी समितियों और विकास संगठनों के सहयोग से संस्थागत क्षमता निर्माण, डिजिटल ग्रामीण वित्त और समावेशी बुनियादी ढाँचे में अपनी अग्रणी स्थिति को मज़बूत किया।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. IGPL का शुभारंभ युवराज सिंह के सह-स्वामी और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हुआ।

जुलाई 2025 में, भारतीय गोल्फ प्रीमियर लीग (IGPL) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह सह-मालिक और ब्रांड एंबेसडर के रूप में शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य भारत में गोल्फ में क्रांति लाना है।

• प्रसिद्ध क्रिकेट ऑलराउंडर और उत्साही गोल्फ खिलाड़ी युवराज सिंह ने आधिकारिक तौर पर इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (IGPL) के सह-मालिक और ब्रांड एंबेसडर की भूमिका संभाल ली है, जो इस श्रृंखला के लिए एक बड़ा बढ़ावा है।

• जनवरी-फरवरी 2026 में शुरू होने वाले IGPL में चार सप्ताह तक "होम-एंड-अवे" मॉडल के साथ छह फ्रेंचाइजी टीमें भाग लेंगी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

• IGPL ने भारतीय गोल्फ संघ (IGU) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और भारतीय महिला गोल्फ संघ (WGAI) के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य उभरती प्रतिभाओं, विशेष रूप से शौकिया और महिला गोल्फरों के बीच, को बढ़ावा देना है।

Key Points:-

(i) IGPL के CEO उत्तम सिंह मुंडी ने अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डाला: लीग ने सितंबर 2025 से शुरू होने वाले 10-सप्ताह के दौरे की योजना बनाई है, जिसके बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तैयारी के लिए नवंबर में रणनीतिक खिलाड़ी नीलामी की जाएगी।

(ii) लीग में मिश्रित लिंग वाली टीमें होंगी और एक नया प्रतियोगिता प्रारूप होगा - सुबह "टर्फ वार्स" मैच-प्ले और शाम को "एक्स-गोल्फ" रिले प्रारूप - जिसे दर्शकों के आकर्षण और समावेशिता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(iii) IGPL का लक्ष्य जमीनी स्तर और पेशेवर स्तर को जोड़ना है: शौकिया एकीकरण और गोल्फ दिग्गजों से मार्गदर्शन के माध्यम से, युवा भारतीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षण, टूर्नामेंट और अंतर्राष्ट्रीय खेल के अवसरों के माध्यम से प्रदर्शन प्राप्त होगा।

SPORTS

1. बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय Rugby 7s चैम्पियनशिप 2025 में अंडर-18 बालक वर्ग का खिताब जीता।

14 जुलाई, 2025 को, बिहार की अंडर-18 लड़कों की टीम देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित 10वीं जूनियर राष्ट्रीय Rugby 7s चैंपियनशिप में चैंपियन बनकर उभरी, जो भारत में जमीनी स्तर पर रग्बी के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ।

- **भारतीय Rugby फुटबॉल संघ (IRFU) के तहत Rugby इंडिया फेडरेशन ने 12 से 14 जुलाई, 2025 तक देहरादून के गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में जूनियर नेशनल रग्बी सेवंस चैंपियनशिप के 10वें संस्करण का आयोजन किया, जिसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी होगी।**

- **बिहार ने एक नाटकीय फाइनल मैच में ओडिशा को 17-15 से हराकर अंडर-18 बालक वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया। खेल को जीत दिलाने वाला यह प्रयास आखिरी कुछ सेकंड में आया, जिसने बिहार की शानदार वापसी और दृढ़ संकल्प को दर्शाया।**

Key Points:-

(i) बिहार की टीमों को उनके तकनीकी अनुशासन, आक्रामक टैकल और तेज़-तर्रार आक्रमण के लिए सराहा गया। लड़कों की टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे पारंपरिक Rugby केंद्रों से बेहतर प्रदर्शन किया।

(ii) विजेता टीमों को आनंद कुमार सिंह द्वारा प्रशिक्षित किया गया और बिहार रग्बी एसोसिएशन के तहत रग्बी इंडिया के युवा विकास कार्यक्रम द्वारा समर्थित मार्गदर्शन दिया गया। इस कार्यक्रम ने 2020 से बिहार को रग्बी प्रतिभा केंद्र के रूप में उभरने में मदद की है।

(iii) 2025 की चैंपियनशिप अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए Rugby इंडिया के रोडमैप में एक रणनीतिक भूमिका निभाती है, विशेष रूप से एशियाई यू 18 सेवन्स चैंपियनशिप और 2026 के लिए नियोजित युवा राष्ट्रमंडल रग्बी कार्यक्रम की तैयारी में।

AWARDS

1. 2024 में बाढ़ के बावजूद विजयवाड़ा को शीर्ष सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार प्राप्त हुआ।

विजयवाड़ा नगर निगम ने 2024 में विनाशकारी बाढ़ के बाद भी स्वच्छता मानकों को बनाए रखते हुए उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया।

• विजयवाड़ा को सुपर स्वच्छ लीग के लिए '10 लाख से अधिक जनसंख्या' श्रेणी में चुना गया है, जिससे वह इंदौर, नवी मुंबई और सूरत जैसे प्रतिष्ठित शहरों में शामिल हो गया है। पुरस्कार समारोह 17 जुलाई 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जहाँ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पुरस्कार प्रदान करेंगे।

• सितंबर 2024 में, विजयवाड़ा कृष्णा और बुदमेरु नदियों में भारी वर्षा के कारण आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुआ, जिससे 2,70,000 से ज़्यादा निवासी प्रभावित हुए और कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद, शहर ने बाढ़ से संबंधित कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया और स्वच्छता की निरंतरता के लिए प्रशंसा अर्जित की।

• बाढ़ के बाद की सफाई में 10,000 से ज़्यादा सफ़ाई कर्मचारी, 200 से ज़्यादा अधिकारी, और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और स्वच्छ आंध्र निगम का नेतृत्व शामिल था। उन्होंने बाढ़ का मलबा साफ़ किया, नहरों और नालों को साफ़ किया, और सफ़ाई व्यवस्था को तेज़ी से बहाल किया, जिससे शहर की सफ़ाई की प्रतिष्ठा बच गई।

Key Points:-

(i) विजयवाड़ा ने घर-घर कचरा संग्रहण और सार्वजनिक शौचालयों की शत-प्रतिशत सफ़ाई में लगभग 99% की उपलब्धि हासिल की और ODF (खुले में शौच मुक्त) प्रमाणपत्र प्राप्त किया। इसने 100% स्रोत पृथक्करण भी हासिल किया। हालाँकि इसकी राष्ट्रीय रैंकिंग में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन यह पूरे भारत में शीर्ष 10 में बना रहा।

(ii) विजयवाड़ा को मिला पुरस्कार आंध्र प्रदेश की व्यापक सफलता का एक हिस्सा है—विशाखापत्तनम, गुंटूर, तिरुपति और राजामहेंद्रवरम सहित पाँच शहरों को पुरस्कार मिले। यह स्वच्छ आंध्र - स्वर्ण आंध्र मिशन के तहत मज़बूत भागीदारी को दर्शाता है और शहरी स्वच्छता एवं स्थिरता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

2. ज़ेप्टो के आदित पालीचा और कैवल्य वोहरा एवेंडस वेल्थ-हुरुन इंडिया U30 एंटरप्रेन्योर्स लिस्ट 2025 में नंबर 1 स्थान दिया गया।

17 जुलाई 2025 को, ज़ेप्टो के सह-संस्थापक आदित पलिचा और कैवल्य वोहरा (दोनों 22) को 79 समकक्षों

से आगे, प्रथम एवेंडस वेल्थ-हुरुन इंडिया अंडर-30 (U30) उद्यमी सूची 2025 में संयुक्त रूप से #1 स्थान दिया गया।

• आदित पलिचा और कैवल्य वोहरा ने U30 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तथा वे सबसे युवा उद्यमी (उम्र 22 वर्ष) के रूप में उभरे हैं, जो भारत के किराना वितरण बाजार को नया आकार देने वाले त्वरित-वाणिज्य मंच का नेतृत्व कर रहे हैं।

• इस प्रथम U30 संस्करण में तकनीक, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में 30 वर्ष से कम आयु के 79 उत्कृष्ट नवप्रवर्तकों का परिचय दिया गया है - जो युवा-संचालित आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है।

• सामूहिक रूप से, U30 संस्थापकों ने इक्विटी के रूप में 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऋण के रूप में 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं, और 64,000 से अधिक नौकरियां पैदा की हैं, जो भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके मजबूत प्रभाव को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) एवेंडस वेल्थ-हुरुन इंडिया U30 एंटरप्रेन्योर्स लिस्ट 2025 का उद्देश्य भारत के 30 वर्ष से कम आयु के सबसे प्रभावशाली युवा उद्यमियों को उजागर करना है जो नवाचार, मूल्य सृजन और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पहले संस्करण में उन संस्थापकों को शामिल किया गया है जिन्होंने व्यवसाय विस्तार, उद्यम पूंजी जुटाने और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। यह सूची हुरुन इंडिया के प्रमुख प्रकाशनों, जैसे हुरुन रिच लिस्ट और हुरुन इंडिया स्टार्टअप इंडेक्स, का युवा-केंद्रित विस्तार है, जो दीर्घकालिक उद्यमशीलता प्रभाव पर ज़ोर देता है।

(ii) मुंबई 15 उद्यमियों के साथ शहरवार रैंकिंग में शीर्ष पर है, महाराष्ट्र 21 उद्यमियों के साथ राज्यवार सूची में शीर्ष पर है, तथा 79 संस्थापकों में से 66 स्व-निर्मित प्रथम पीढ़ी के उद्यमी हैं।

(iii) केवल छह महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है; सबसे कम उम्र की महिला, देविका घोलप (28) को उनके AI-आधारित डिजिटल पैथोलॉजी स्टार्टअप के लिए सम्मानित किया गया। समूह की औसत आयु केवल 28 वर्ष है।

3. दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

भारत ने 5-14 जुलाई, 2025 तक दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड (IChO) में असाधारण सफलता हासिल की, जिसमें दो स्वर्ण और दो रजत पदक हासिल किए।

• भारतीय छात्र देवेश पंकज भैया (जलगांव, महाराष्ट्र) और संदीप कुची (हैदराबाद, तेलंगाना) ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि देबदत्त प्रियदर्शी (भुवनेश्वर, ओडिशा) और उज्ज्वल केसरी (नई दिल्ली) ने रजत पदक अर्जित किए।

• ओलंपियाड में 90 देशों के 354 छात्रों ने भाग लिया। भारत ने यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इजरायल के साथ समग्र पदक तालिका में संयुक्त रूप से छठा स्थान हासिल किया।

Key Points:-

(i) यह 1999 के बाद से भारत की लगातार 26वीं

भागीदारी है। पिछले दशक में, भारतीय छात्रों ने उल्लेखनीय सुधार किया है, स्वर्ण और रजत पदक दर क्रमशः 38% और 58% तक बढ़ गई है।

(ii) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के अंतर्गत होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (HBCSE) द्वारा स्थापित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की चयन प्रक्रिया शामिल थी। इसमें प्रोफेसर अंकुश गुप्ता (मुख्य मेंटर), प्रोफेसर सीमा गुप्ता, डॉ. नीरजा दशपुत्रे और डॉ. अमृत मित्रा ने मार्गदर्शन प्रदान किया।

(iii) IChO 2025 की विश्व स्तरीय आयोजन के लिए प्रशंसा की गई, जिससे वैश्विक शैक्षणिक उत्कृष्टता और विज्ञान कूटनीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत हुई।

IMPORTANT DAYS

1. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 2025- 17 जुलाई को मनाया गया।

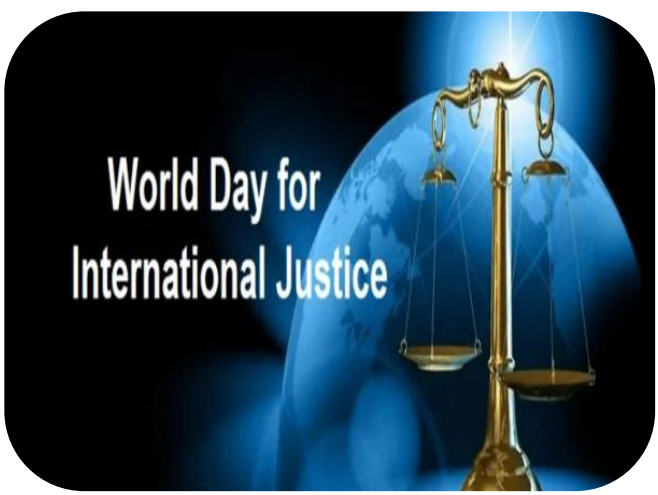

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस या विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 17 जुलाई 2025 को रोम संविधि को अपनाने की 27वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का गठन हुआ।

• यह दिवस 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने की याद में मनाया जाता है, जिसके तहत नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों जैसे गंभीर अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए एक स्थायी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय और मानवाधिकारों को बनाए रखने की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

• 2025 में रोम संविधि की 27वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ICC को आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2002 को लागू किया गया था, जब यह संविधि आवश्यक संख्या में देशों द्वारा अनुमोदित होने के बाद प्रभावी हुई थी। अब तक, 120 देशों ने इस संविधि का अनुमोदन कर दिया है।

Key Points:-

(i) रोम संविधि, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का आधारभूत कानूनी दस्तावेज़ है, 17 जुलाई 1998 को रोम, इटली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र राजनयिक पूर्णाधिकार सम्मेलन (UNDCP) के दौरान अपनाई गई थी। यह ICC के अधिकार क्षेत्र और कार्यप्रणाली को परिभाषित करती है। हालाँकि, ICC केवल 1 जुलाई 2002 के बाद हुए अपराधों की जाँच कर सकती है, जिस दिन यह संविधि लागू हुई और आधिकारिक तौर पर न्यायालय को क्रियाशील बनाया; इस तिथि से पहले हुई घटनाओं पर इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(ii) इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देना और दंड से मुक्ति के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष की पुष्टि करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय तंत्र और राष्ट्रों के बीच कानूनी सहयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।

(iii) 2010 में, युगांडा के कंपाला में आयोजित रोम संविधि के पहले समीक्षा सम्मेलन के दौरान, सदस्य राज्यों ने आधिकारिक तौर पर 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में घोषित

किया, जिससे दुनिया भर में शांति, सुरक्षा और न्याय का समर्थन करने में इसके महत्व को मान्यता मिली।

DEFENCE

1. भारत ने ओडिशा से पृथ्वी-II और अग्नि-I बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया।

17 जुलाई 2025 को, रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से दो परमाणु-सक्षम, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों—पृथ्वी-II और अग्नि-I—का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सामरिक बल कमान (SFC) द्वारा किए गए इन परीक्षणों ने क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच परिचालन तत्परता और तकनीकी सटीकता को प्रमाणित किया।

• ये प्रक्षेपण सामरिक बल कमान (SFC) के तत्वावधान में किए गए, जो भारत के परमाणु शस्त्रागार के लिए ज़िम्मेदार त्रि-सेवा इकाई है। दोनों मिसाइलों का क्रमिक प्रक्षेपण किया गया, अग्नि-1 का प्रक्षेपण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से और पृथ्वी-2 का प्रक्षेपण चांदीपुर से किया गया, जिससे निवारक क्षमताओं की पुष्टि हेतु एक समन्वित अभ्यास का संकेत मिला।

• पृथ्वी-II एक तरल ईंधन, एकल-चरण मिसाइल है जिसकी अधिकतम सीमा लगभग 350 किमी है, जो 1,000 किलोग्राम तक के पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।

• अग्नि-I एक ठोस ईंधन, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 700-900 किमी है, तथा यह लगभग 1,000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है।

Key Points:-

(i) रक्षा सूत्रों और मंत्रालय ने पुष्टि की कि सभी मिशन उद्देश्य पूरे हो गए हैं और "परिचालन और तकनीकी मापदंडों को मान्य किया गया है", जिसमें रात्रिकालीन क्षमता, लांचर की कार्यप्रणाली, नेविगेशन प्रणाली और पुनः प्रवेश की सटीकता शामिल है - जिससे दोनों वितरण प्रणालियों में विश्वास मजबूत हुआ है।

(ii) यह लगातार मिसाइल परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर—मई 2025 में भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़पों के बाद हुआ है। ये परीक्षण भारत की रणनीतिक स्थिति और निवारक तत्परता को रेखांकित करते हैं, और इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये कम दूरी की परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें भारत की प्रतिक्रियाशील रक्षा रणनीति का अभिन्न अंग बनी हुई हैं।

(iii) इस सफल दोहरे परीक्षण ने भारत की परमाणु नीति में निहित एक मज़बूत, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक रुख़ बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यह सामरिक बल कमान (SFC) की निरंतर परिचालन तत्परता और डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) के अंतर्गत भारत के स्वदेशी मिसाइल विकास की तकनीकी परिपक्वता को भी उजागर करता है।

2. भारतीय नौसेना चार स्वदेशी युद्धपोतों के साथ 32वें सिम्बेक्स 2025 में शामिल होगी, जिससे सिंगापुर के साथ समुद्री संबंध मजबूत होंगे।

जुलाई 2025 में, भारतीय नौसेना ने चार स्वदेश निर्मित जहाजों—आईएनएस दिल्ली, INS सतपुड़ा, INS किल्टन और INS शक्ति—को इस महीने के अंत में सिंगापुर में होने वाले 32वें सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX) में भाग लेने के लिए तैनात किया है। यह अभ्यास भारत के विज़न सागर और एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है, जिससे सहयोग और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

- **पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल सुशील मेनन की कमान में, विध्वंसक आईएनएस दिल्ली, निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट INS सतपुड़ा, आईएनएस किल्टन और सहायक टैंकर आईएनएस शक्ति से युक्त भारतीय स्क्वाड्रन SIMBEX 2025 के लिए सिंगापुर रवाना हुआ। ये पोत भारत की नौसैनिक आत्मनिर्भरता और समुद्री क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।**

Key Points:-

(i) SIMBEX, 1994 में अपनी शुरुआत (जिसे पहले "लायन किंग अभ्यास" कहा जाता था) के बाद से भारत और सिंगापुर के बीच सबसे लंबा निर्बाध वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। दशकों से, यह पनडुब्बी-रोधी युद्ध पर केंद्रित अभ्यास से विकसित होकर वायु रक्षा, सतह-रोधी अभियानों, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और खोज-बचाव अभ्यासों सहित एक व्यापक अभ्यास बन गया है।

(ii) SIMBEX आमतौर पर दो चरणों में होता है: एक बंदरगाह चरण जिसमें पेशेवर आदान-प्रदान, क्रॉस-डेक दौरे, खेल आयोजन और योजना सत्र शामिल होते हैं; उसके बाद एक समुद्री चरण होता है जिसमें लाइव हथियार फायरिंग, पनडुब्बी रोधी अभ्यास (ASW), वायु रक्षा युद्धाभ्यास, संचार अभ्यास और हवा, सतह और पानी के नीचे के क्षेत्रों में सामरिक प्रशिक्षण शामिल होता है। ये अंतर-संचालन और परिचालन तालमेल का निर्माण करते हैं।

(iii) SIMBEX 2025 में भागीदारी, विज़न सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और एक्ट ईस्ट नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो समुद्री डकैती और गैर-सरकारी तत्वों जैसे खतरों के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करती है। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले ने इस अभ्यास को नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देने और भारत-आसियान नौसैनिक सहयोग को मज़बूत करने का अभिन्न अंग बताया।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. स्पेसएक्स ने 24 अमेज़न कुइपर उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित किया, जो प्रोजेक्ट कुइपर का तीसरा मिशन है।

16 जुलाई 2025 को, एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेसएक्स ने अमेज़न के प्रोजेक्ट कुइपर के लिए 24 ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जो इस उपग्रह समूह की तीसरी परिचालन तैनाती थी। यह प्रक्षेपण अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से किया गया।

• यह अमेज़न के प्रोजेक्ट कुइपर के तहत तीसरा ऑपरेशनल लॉन्च था। यह एक उपग्रह-आधारित ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य 3,200 से ज़्यादा लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रहों के नियोजित नेटवर्क के ज़रिए वैश्विक इंटरनेट कवरेज को बढ़ाना है। इस लॉन्च के साथ, तैनात कुइपर उपग्रहों की कुल संख्या 78 हो गई है।

• यह प्रक्षेपण KF-01 (कुइपर फाल्कन 1) मिशन का हिस्सा था और फाल्कन 9 प्रक्षेपण यान पर हुआ, जो अपने पुन: प्रयोज्य प्रथम-चरण बूस्टर के लिए जाना जाता है। यह मिशन फ्लोरिडा स्थित एक प्रमुख अमेरिकी प्रक्षेपण केंद्र, केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से शुरू हुआ।

• यह आयोजन नासा के ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की 56वीं वर्षगांठ के साथ हुआ, जिसने 16 जुलाई 1969 को मानवता को पहली बार चंद्रमा पर पहुंचाया था। यह प्रतीकात्मक समय आधुनिक वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण की निरंतर विरासत को पुष्ट करता है।

Key Points:-

(i) प्रक्षेपण के बाद, सभी 24 उपग्रहों को 465 किलोमीटर ऊँची कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। इन उपग्रहों को धीरे-धीरे 630 किलोमीटर की परिचालन ऊँचाई तक पहुँचाया जाएगा, जिससे इष्टतम ब्रॉडबैंड कवरेज क्षमताएँ प्राप्त होंगी।

(ii) प्रोजेक्ट कुइपर के लिए अमेज़न के मिशन नियंत्रण का मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, अमेरिका में है। इस सुविधा से, इंजीनियर वास्तविक समय में तैनात उपग्रहों की ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड संचालन की निगरानी करते हैं।

(iii) स्पेसएक्स का उपग्रह प्रभाग, स्टारलिंक, वर्तमान में लगभग 8,000 LEO उपग्रहों का संचालन करता है और दुनिया भर में लाखों उपग्रहों को सेवाएँ प्रदान करता है। इसके विपरीत, अमेज़न अभी भी प्रारंभिक तैनाती चरण में है, लेकिन 2025 के अंत तक अपने पूरे समूह को लॉन्च करने और सेवाएँ शुरू करने की योजना बना रहा है।

Static GK

Indian Navy (IN)	वर्तमान नौसेनाध्यक्ष (CNS): एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी	मुख्यालय: नई दिल्ली
Gujarat	मुख्यमंत्री: भूपेन्द्र पटेल	राज्यपाल: आचार्य देवव्रत
IRDAI	अध्यक्ष: देबाशीष पांडा	मुख्यालय: हैदराबाद
Tesla	CEO : एलोन मस्क	मुख्यालय: ऑस्टिन, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)	अध्यक्ष: शाजी के.वी.	मुख्यालय: मुंबई
Hurun India	संस्थापक और मुख्य शोधकर्ता : अनस रहमान जुनैद	मुख्यालय: मुंबई
Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX)	CEO : एलोन रीव मस्क	मुख्यालय : टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
International Criminal Court (ICC)	अध्यक्ष : न्यायाधीश तोमोको अकाने	मुख्यालय : द हेग, नीदरलैंड